RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 10 NOVEMBER TO 16 NOVEMBER 2021 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 07 ■ अंक 10 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

फिर तेजी से चढ़ रहा है कच्चा तेल Page 2

सरकारी तेल कंपनियां 22,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन लगाएंगी Page 4

रेट्रो, रस्टिक और खूबसूरत : तिस्वा फैमिली की नई लाइट्स Page 7

editoria!

बढ़ता डिजिटालाईजेशन

अर्थव्यवस्था में नगदी की जगह डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने की हो रही कोशिशें कामयाब होती दिख रही हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शोध रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में अनौपचारिक आर्थिकी का हिस्सा महज 15 से 20 फीसदी रह गया है. वर्ष 2018 में यह आंकड़ा 52.4 प्रतिशत था. पांच साल पहले हुई नोटबंदी के बाद किये गये उपायों तथा महामारी के दौरान पैदा हुए हालात ने इसमें बड़ा योगदान किया है. अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण नोटबंदी के मुख्य उद्देश्यों में था. जन-धन खाता, लाभुकों के खाते में भुगतान, मोबाइल बैंकिंग का प्रसार, ई-श्रम पोर्टल आदि से इस उद्देश्य को पाने में सहयोग मिला है. छोटे-से-छोटे कारोबारी और कामगार के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं चलायी हैं. उल्लेखनीय है कि नोटबंदी, जीएसटी और फिर महामारी से सबसे अधिक प्रभावित अनौपचारिक सेक्टर ही हुआ था. डिजिटलीकरण से इस सेक्टर को कर्ज, बीमा, बचत आदि से संबंधित बेहतर अवसर प्राप्त हुए हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल भुगतान सूचकांक भी इसे इंगित करता है. इसी के साथ, नकली नोटों का चलन भी बहुत कम हो गया है. साल 2019 में 3.1 लाख नकली नोटों की पहचान हुई थी, पर अब यह आंकड़ा दो लाख पर आ गया है. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण तथा भविष्य निधि खातों की संख्या में वृद्धि भी डिजिटल लेन-देन के महत्व को रेखांकित करती है. पर, अभी भी नगदी का चलन उच्च स्तर पर है. वित्त वर्ष 2020-21 में यह चलन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 14.5 प्रतिशत है. हालांकि 2018 से ही इसमें बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अभी इसकी सबसे बड़ी वजह महामारी रही है, जब एक ओर लॉकडाउन व अन्य कारणों से जीडीपी में भारी संकुचन आया, वहीं दूसरी ओर नगदी की मांग बढ़ गयी. यह मांग अभी भी बनी हुई है और इसे नीचे आने में कुछ समय लग सकता है. यह स्थिति पूरी दुनिया में है. अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने के साथ-साथ इसमें सुधार के संकेत भी मिलने लगे हैं. बीते 29 अक्तूबर को नगदी का चलन बजट में आकलित वित्त वर्ष 2022 की जीडीपी का 13.2 प्रतिशत था. जानकारों का मानना है कि आर्थिक गतिविधियों के तेज होने, बाजार में मांग व आपूर्ति बढ़ने तथा मुद्रास्फीति में कमी होने के साथ यह चलन भी नीचे आयेगा. यह भी समझा जाना चाहिए कि डिजिटल भुगतान करनेवाले लोग भी आम उपभोक्ता होते हैं, जो बहुत सारी खरीदारी नगदी में करते हैं. डिजिटल संसाधनों का समुचित विकास अभी कस्बों और गांवों में अपेक्षित ढंग से नहीं पहुंच सका है. मोबाइल और इंटरनेट के विस्तार के साथ इस अभाव को कम किया जा सकता है. बैंकों समेत वित्तीय संस्थाओं और वित्तीय तकनीक की कंपनियों को व्यावहारिक चुनौतियों के समाधान के लिए अधिक सक्रिय होना चाहिए. उम्मीद की जानी चाहिए कि सुधारों की गति बरकरार रखते हुए सरकार भी नियमन और निगरानी को लेकर मुस्तैद बनी रहेगी.

भारत में रिकॉर्ड डिजिटल लेनदेन

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश मं डिजिटल इंडिया की राह मजबूत होती जा रही है। भारतीय तेज रफ्तार से डिजिटल पेमेंट मोड को अपना रहे हैं। इस सारी कहानी को आंकड़े बयां कर रहे हैं। अगर अक्टूबर की बात करें, तो इस माह भारत में रिकॉर्ड डिजिटल पेमेंट हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर माह में कुल 421 करोड़ ळझ्ड पेमेंट के जरिए 7.71 लाख करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है। यह एक रिकॉर्ड है। जब अक्टूबर माह में सबसे ज्यादा बार ळझ्ड पेमेंट और सबसे ज्यादा रुपये का यूपीआई ट्रांजैक्शन किया गया है। अगर यूपीआई पेमेंट की बात करें, तो इसमें

फोन पे पहले पायदान पर है। फोन पे से अक्टूबर माह में 193 करोड़ यूपीआई लेनदेन हुये, जो कि सितंबर के 165 करोड़ से 19 फीसदी ज्यादा है। सितंबर में जहां 3.06 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ था, जो अक्टूबर में बढ़कर 3.65 लाख करोड़ रुपये हो गया। फोन पे का कुल यूपीआई पेमेंट में सबसे ज्यादा 47 फीसदी हिस्सेदारी रही है।

गूगल पे से अक्टूबर माह में 145 करोड़ यूपीआई पेमेंट हुये हैं, जो कि पिछले माह से 12 फीसदी ज्यादा है, जबकि ट्रांजैक्शन वैल्यू में 15 फीसदी ज्यादा है। इस दौरान 2.87 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है। गूगल पे का मार्केट शेयर करीब 34 फीसदी रहा है। इसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक तीसरा सबसे बड़ा यूपीआई प्लेयर बनकर उभरा है। इमसें पिछले माह के मुकाबले 34 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया है। पेटीएम से 80,508 करोड़ लेनदेन हुये हैं। इस दौरान मार्केट शेयर 10 फीसदी रहा है।

यूपीआई पेमेंट के मामले में व्हाट्सएप्प पे का लगातार दूसरे माह डबल ट्रांजैक्शन हुआ है। यह सितंबर के 10 लाख से बढ़कर 26 लाख हो गया है। व्हाट्सएप्प पे पिछले माह के 62.31 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर 104 करोड़ रुपये हो गया है। एनपीसीआई के दिशा-निर्देशों के मुताबिक व्हाट्सएप्प यूपीआई फीचर 20 मिलियन यूजर तक ही सीमित है।

और भी सस्ता होगा पेट्रोल डीजल!

कच्चे तेल के उत्पादन को लेकर 'ओपेक प्लस' ने लिया ये फैसला

फ्रैंकफर्ट। एजेंसी

कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रयासों को झटका लगा है। गुरुवार को ओपेक और संबद्ध तेल उत्पादक देशों की बैठक में तेल उत्पादन बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने सऊदी अरब और रूस से उत्पादन बढ़ाने तथा यूएस गैसोलीन कीमतों को कम करने का आग्रह किया था। 'ओपेक प्लस' गठबंधन, सउदी नेतृत्व में ओपेक सदस्यों और रूस के नेतृत्व में अन्य देशों से मिलकर बना है।

हालांकि ओपेक + गठबंधन ने दिसंबर के महीने के लिए प्रति दिन 400,000 बैरल के उत्पादन में वृद्धि को मंजूरी दी है। यह फैसला अगले साल हर महीने बाजार में इतनी मात्रा में तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए समूह के रोड मैप के अनुरूप है। जब तक कोरोनोवायरस महामारी के दौरान किए गए उत्पादन में कटौती को बहाल नहीं किया जाता है, तब तक पेट्रोलियम उत्पादन को थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ाने की योजना है। गठबंधन कोरोना वायरस महामारी के दौरान उत्पादन में की गई कटौती को बहाल करने के लिए सावधानी से आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते कच्चा तेल सात साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। बाइडन ने बार-बार गठबंधन से उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा है, हालांकि अभी तक इसमें अधिक सफलता नहीं मिली।

विदेशी मुद्रा भंडार 1.9 अरब डॉलर बढ़कर 642 अरब डॉलर पर

मुंबई। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 29 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में 1.91 अरब डॉलर बढ़कर 642.01 अरब डॉलर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को अपने ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी। यह वृद्धि विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा सोने के मूल्य में पर्याप्त वृद्धि की वजह से संभव हुई। इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 90.8 करोड़ डॉलर घटकर 640.1 अरब डॉलर रह गया था। रिजर्व बैंक ने कहा कि आलोच्य सप्ताह में भारत की विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए) 1.36 अरब डॉलर बढ़कर 578.46 अरब डॉलर हो गईं। डॉलर में बताई जाने वाली विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में यूरो, पाउंड और येन जैसी दूसरी विदेशी मुद्राओं के मूल्य में वृद्धि या कमी का प्रभाव भी शामिल है। समीक्षाधीन सप्ताह में स्वर्ण आरक्षित भंडार का मूल्य 57.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 39.01 अरब डॉलर हो गया। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष में देश का विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 1.7 करोड़ डॉलर बढ़कर 19.30 अरब डॉलर हो गया। आईएमएफ में देश का आरक्षित विदेशी मुद्रा भंडार 10 लाख डॉलर बढ़कर 5.24 अरब डॉलर हो गया।

पेट्रोनेट का दूसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 11 प्रतिशत घटकर 823 करोड़ रुपये

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश की सबसे बड़ी तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयातक पेट्रोनेट एलएनजी लि. का सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 11.24 प्रतिशत घटकर 823.02 करोड़ रुपये रह गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 927.3 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी आय 70 प्रतिशत बढ़कर 10,894.72 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। कंपनी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से उसका एलएनजी कार्गो आयात कम रहा। कंपनी ने अनुबंधित सीमा से बाहर कम एलएनजी का आयात किया क्योंकि घरेलू ग्राहक इतनी ऊंची कीमत वहन नहीं कर सकते हैं। पेट्रोनेट के निदेशक मंडल ने 2021-22 के लिए सात रुपये प्रति शेयर के विशेष अंतरिम लाभांश की घोषणा की है।

जन-धन योजना के तहत बीमा कवर वाले 31.67 करोड़ रुपे कार्ड जारी

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

बैंकों ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत खाताधारकों को मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर देने वाले 31.67 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि अगस्त 2014 में यह योजना शुरू होने के बाद से अब तक 43.76 करोड़ जन-धन खाते खोले जा चुके हैं। मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने एक ट्वीट में कहा, "प्रत्येक वयस्क नागरिक को बैंकिंग सुविधा देने के लिए शुरू इस अभियान में 21 अक्टूबर, 2021 तक जन-धन खाताधारकों को मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर देने वाले 31.67 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 के अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जन-धन योजना शुरू करने की घोषणा की थी और उसके कुछ दिनों बाद ही इसे लागू कर दिया गया था। वर्ष 2018 में सरकार ने बढ़ी हुई सुविधाओं वाली जन-धन योजना 2.0 शुरू की थी जिसमें 'हरेक परिवार' के बजाय 'हरेक वयस्क नागरिक' को बैंकिंग दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया। रुपे डेबिट कार्ड पर दिए जाने मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर को भी दोगुना कर 2 लाख रुपये कर दिया गया था। मार्च, 2015 के अंत में इस योजना के तहत खुले खातों की संख्या 14.72 करोड़ थी, जो अक्टूबर, 2021 में बढ़कर 43.76 करोड़ हो गई। करीब 55 प्रतिशत खाताधारक महिलाएं हैं।

News यू केन USE

शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे टूटकर 74.16 पर पहुंचा

मुंबई। एजेंसी

घरेलू शेयर बाजारों में नरमी और अमेरिकी मुद्रा में मजबूती की वजह से रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे टूटकर 74.16 पर पहुंच गया। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय में, रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर रुख के साथ 74.11 पर खुला। इसके बाद रुपया और नीचे गिरकर 74.16 पर पहुंच गया जो पिछले बंद के मुकाबले 11 पैसे की गिरावट को दिखाता है। मंगलवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 74.05 पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.08 प्रतिशत चढ़कर 94.03 पर आ गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.29 प्रतिशत की तेजी के साथ 85.03 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

रिलायंस इंडस्ट्रीज अमेरिका में अपनी शैल गैस संपत्तियां बेचेगी

नयी दिल्ली। एजेंसी

रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) ने ईगलफोर्ड की शैल गैस संपत्तियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की सहमति दे दी है। इसके साथ कंपनी अमेरिका में शैल गैस के कारोबार से निकल गयी है। हालांकि, इस सौदे के मूल्य का खुलासा नहीं हुआ है। रिलायंस ने 2010 और 2013 के बीच शेवरॉन, पायनियर नैचुरल रिसोर्स और कैरिजो ऑयल एंड गैस के साथ तीन अपस्ट्रीम खोज संयुक्त उपक्रमों और पायनियर के साथ एक मिडस्ट्रीम संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी खरीदी थी। मिडस्ट्रीम का आशय हाइड्रोकार्बन के प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन और विपणन से है। कंपनी ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की अनुषंगी की अनुषंगी रिलायंस ईगलफोर्ड अपस्ट्रीम होल्डिंग, एलपी ने ईगलफोर्ड शैल की संपत्तियों में अपनी हिस्सेदारी के विनिवेश के लिए एनसाइन ऑपरेटिंग 3, एलएलसी के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। इस लेनदेन के साथ रिलायंस ने उत्तरी अमेरिका में अपनी सभी शैल गैस संपत्तियां बेच दी हैं और शेल गैस के कारोबार से निकल गयी है।

वित्त मंत्रालय ने उद्योग और व्यापार निकायों से कराधान पर सुझाव आमंत्रित किए

नयी दिल्ली। एजेंसी

वित्त मंत्रालय ने 2022-23 के बजट के लिए उद्योगों और व्यापार निकायों से कराधान पर सुझाव मांगे हैं। आम बजट कोविड-19 महामारी से प्रभावित भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दिशा तय करने वाला होगा। व्यापार और उद्योग संगठनों को भेजे पत्र में मंत्रालय ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों की शुल्क संरचना में बदलाव, दरों और कर आधार को व्यापक करने के बारे में सुझाव आमंत्रित किए हैं। उद्योग संगठनों को अपने सुझावों के साथ यह भी बताना होगा कि आर्थिक रूप से इनकी क्यों जरूरत है। मंत्रालय को सुझाव 15 नवंबर, 2021 तक भेजे जा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा, ''आपके सुझावों और विचारों में उत्पादन, कीमतों, सुझाए गए परिवर्तनों के राजस्व प्रभाव का उल्लेख होना चाहिए और आपके प्रस्ताव का समर्थन करने वाली प्रासंगिक सांख्यिकीय जानकारियों का भी उल्लेख होना चाहिए।'' 2022-23 का बजट अगले साल एक फरवरी को संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। यह मोदी 2.0 सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चौथा बजट होगा।

डीजल-पेट्रोल ही नहीं क्रूड ऑयल से निकलती हैं ये 12 चीजें

कच्चा तेल महंगा होते ही बढ़ जाती हैं इनकी कीमतें!

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

कच्चे तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे डीजल और पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के चलते सिर्फ डीजल-पेट्रोल ही नहीं, बल्कि बहुत सारी अन्य चीजें भी महंगी हो रही हैं। घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें भी काफी हद तक इसी का नतीजा हैं। कच्चे तेल से सिर्फ डीजल-पेट्रोल ही नहीं निकलते हैं, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें निकलती हैं। आइए जानते हैं कच्चे तेल से निकलने वाली 12 अहम चीजों के बारे में।

1- एलपीजी गैस

जब कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है तो पहले चरण में इससे ब्यूटेन और प्रोपेन नाम की प्राकृतिक गैसें मिलती हैं। इनका इस्तेमाल कुकिंग के लिए और ट्रांसपोर्ट में होता है। प्रोपेन को ही अधिक दबाव में ब्यूटेन के साथ कंप्रेस किया जाता है, जिससे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी बनती है। एलपीजी गैस ही घरेलू गैस सिलेंडरों में भरी जाती है।

2-3-4. पेट्रोल, डीजल और एटीएफ

अगले चरण में प्रोपेन गैस को अलग-अलग कर के पेट्रोल, केरोसिन और डीजल तीनों चीजें निकाली जाती हैं। इन सबमें सबसे शुद्ध पेट्रोल ही होता है और इसी वजह से ये सबसे महंगा भी होता है। केरोसीन को कई चरणों में रिफाइन कर के हवाई जहाज का ईंधन यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल तैयार किया जाता है। इसमें एक खास तरह का कैमिकल भी मिलाया जाता है, ताकि जब विमान बहुत ऊंचाई पर हवा में हो तो तापमान 50-60 डिग्री माइनस में जाने के बावजूद वह जमे नहीं। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि एटीएफ में एक भी बूंद पानी की ना हो।

5- नैफ्था

पेट्रोल, डीजल और केरोसीन की रिफाइनिंग के बाद जो उत्पाद बचता है, उसे नैफ्था कहते हैं। बाजार में जो पॉकेट लाइटर बिकते हैं, उनमें नैफ्था का ही इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इंडस्ट्रीज में स्टीम क्रैकिंग के लिए भी नैफ्था का इस्तेमाल होता है। यानी डीजल-पेट्रोल मिलने के बाद भी बचे हुए नैफ्था का काफी इस्तेमाल होता है और इसकी भी कीमत कच्चे तेल की कीमत पर निर्भर करती है। कीड़ो से बचाव में कई जगह नैफ्था सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है।

6- नैपाम

कच्चे तेल से नैपाम नाम का एक प्रोडक्ट भी मिलता है। यह विस्फोटक का काम करता है। इसका इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है, जब आग को बहुत दूर तक भेजना होता है, क्योंकि यह धीरे-धीरे लेकिन लगातार जलता है। अगर इसकी जगह पेट्रोल या केरोसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आग दूर तक नहीं जा पाएगी, क्योंकि एक तो वह तेजी से जलते हैं और तेजी से वाष्पीकृत भी होते हैं।

7- मोबिल ऑयल

कच्चे तेल से ही मोटर ऑयल या मोबिल ऑयल मिलता है। इसका इस्तेमाल तमाम गाड़ियों के इंजन में किया जाता है। इससे इंजन की गरारियों या अन्य हिस्सों में कम घर्षण होता है, जिससे वह लंबे समय तक चलते हैं और साथ ही इससे इंजन भी ठंडा रहता है। अगर बिना मोबिल ऑयल के गाड़ी चलाई जाए तो आपसी घर्षण से पुर्जे बहुत तेजी से घिसने लगेंगे और टूटने की भी आशंका बनी रहती है। यहां तक कि अत्यधिक घर्षण के चलते गाड़ी में आग भी लग सकती है।

8- ग्रीस

कच्चे तेल से मोटर ऑयल निकालने के साथ-साथ उससे बहुत सारा ग्रीस भी निकलता है। इस ग्रीस का इस्तेमाल भी घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। ग्रीस जमे हुए घी जैसा पदार्थ होता है। इसे उन पुर्जों का घर्षण कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर मोबिल ऑयल डालना आसान नहीं होता है। मोबिल ऑयल कंटेनर में पड़ता है, लेकिन ग्रीस कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे दरवाजों के लॉक में, मशीनों के बैरिंग में और भी तमाम जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

9- पेट्रोलियम जेली

आपको शायद इस बात का अंदाजा भी ना हो कि जो वैसलीन लगाकर आप ठंड में अपने हाथ-पैर और होंठ मुलायम बनाते हैं, वह भी दरअसल कच्चे तेल से ही निकलती है। ये ग्रीस को बहुत अधिक रिफाइन करने के बाद मिलती है, जिसे कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, इसे बनाते वक्त यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि उसमें कोई हानिकारक कैमिकल ना बचा हो।

10- मोम

कभी न कभी आपके भी मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर मोम कहां से आती है? दरअसल, मोम का उत्पादन भी कच्चे तेल की रिफाइनिंग प्रोपेस में ही होता है। यह कच्चे तेल का एक बायप्रोडक्ट है, जो तमाम चीजें बनाने के दौरान निकलता है। मोम के इस्तेमाल से मोमबत्ती बनाई जाती है, जिससे घरों को रोशन किया जाता है वो भी बिना किसी तरह के धुएं के।

11- कोलतार

आपने भी अक्सर ही सड़कें बनती हुई देखी होंगी। उसमें आपको गाढ़े काले रंग के बेहद चिपचिपे पदार्थ वाला डामर देखने को मिलता है, जिसमें गिट्टियों को लपेटकर सड़क पर बिछाया जाता है। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ सड़क बनती है, बल्कि छत को ढकने वाली वॉटरप्रूफ पट्टियां भी बनाई जाती हैं। डामर को चारकोल, असफाल्ट और कोलतार नाम से भी जाना जाता है। देखा जाए तो रिफाइनिंग के बाद बचा हुए वेस्ट होता है।

12- प्लास्टिक

कच्चे तेल का इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने में भी होता है। दुनिया भर में मिलने वाले अधिकतर प्लास्टिक का उत्पादन कच्चे तेल से ही किया जाता है। वैसे तो वनस्पति तेल से भी प्लास्टिक बनाया जाता है, लेकिन यह कच्चे तेल से निकले प्लास्टिक की तुलना में काफी महंगा पड़ता है। यानी देखा जाए तो कच्चे तेल से सिर्फ डीजल-पेट्रोल नहीं, बल्कि 12 तरह की मुख्य चीजें निकलती हैं। कच्चा तेल महंगा होता है तो इन सभी पर उसका असर होता है।

फिर तेजी से चढ़ रहा है कच्चा तेल

नई दिल्ली। दुनिया भर में कच्चे तेल की मांग बढ़ ही रही है। इस बीच कच्चे तेल के सबसे बड़े उपभोक्ता, अमेरिका में भी इसकी मांग बढ़ी है। तभी तो छह सप्ताह के बाद इस सप्ताह वहां क्रूड ऑयल इंवेंट्री से कच्चे तेल का ड्रॉ हुआ है। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीच्यूट के मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते सप्ताह 2.485 मिलियन कच्चे तेल का ड्रॉ हुआ है। इससे मंगलवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत एक बार फिर से 85 डॉलर प्रति बैरल के करीब चली गई। जहां तक घरेलू बाजार की बात है तो यहां लगातार छठे दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। सरकारी तेल कंपनी आईओसी के पंप पर बुधवार को पेट्रोल की कीमत 103.87 रुपये और डीजल की कीमत 86.67 रुपये पर टिका रहा।

26 दिन में 8.15 रुपये महंगा हुआ था पेट्रोल

बीते सितंबर महीने की 28 तारीख को पेट्रोल जहां 20 पैसे महंगा हुआ था वहीं डीजल भी 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। दरअसल, सितंबर के अंतिम दिनों से जो पेट्रोल की कीमतें बढ़नी शुरू हुई, वह पिछले हफ्ते मंगलवार को थमी थी। हां, बीच में कुछ दिनों के लिए भी इसे जरूर

विराम मिला। पेट्रोल की कीमतों में देखें तो बीते 26 दिनों में ही यह 8.15 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका था।

डीजल 9.45 रुपये महंगा हुआ था

पिछले महीने पेट्रोल के मुकाबले डीजल का बाजार ज्यादा तेज हुआ था। कारोबारी लिहाज से देखें तो पेट्रोल के मुकाबले डीजल बनाना महंगा पड़ता है। लेकिन भारत के खुले बाजार में पेट्रोल महंगा बिकता है और डीजल सस्ता बिकता है। बीते 24 सितंबर से यहां जो डीजल में आग लगनी शुरू हुई वह पिछले हफ्ते मंगलवार को रूकी थी। हालांकि, बीच में कुछ दिनों इसमें विराम भी रहा था। इस दौरान पेट्रोल के मुकाबले डीजल ज्यादा महंगा हुआ था। बीते 29 दिनों में ही यह 9.35 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है।

कच्चे तेल में तेजी

इस समय दुनिया भर में कच्चे तेल की मांग बढ़ ही रही है। इस बीच कच्चे तेल के सबसे बड़े उपभोक्ता, अमेरिका में भी इसकी मांग बढ़ी है। तभी तो छह सप्ताह के बाद इस सप्ताह वहां क्रूड ऑयल इंवेंट्री से कच्चे तेल का ड्रॉ हुआ है। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीच्यूट के मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते सप्ताह 2.485 मिलियन कच्चे तेल का ड्रॉ हुआ है। इससे मंगलवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत एक बार फिर से 85 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई। इस दिन कारोबार की समाप्ति पर ब्रेंट क्रूड की कीमत 1.14 डॉलर चढ़ कर 84.78 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया। पिछले हफ्ते इसमें 2 फीसदी की गिरावट आई थी। डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल तो 2.01 डॉलर की तेजी के साथ 84.15 डॉलर पर पहुंच गया।

'पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के तहत नहीं लाने के कारणों को करें स्पष्ट'- केरल हाई कोर्ट

काउंसिल से 10 दिनों के भीतर मांगा जवाब

एजेंसी।

केरल हाई कोर्ट ने गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) काउंसिल से पूछा कि पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी के तहत क्यों नहीं आ सकते हैं और इस पर परिषद को 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिसि एस मणिकुमार और जस्टिस साजी पी चेली की डिविजन बेंच ने जीएसटी काउंसिल को निर्देश दिया कि वो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाने के कारणों को स्पष्ट करे। यह जनहित याचिका केरल प्रदेश गांधी दर्शनवादी नाम के संगठन की तरफ से दाखिल की गई है। संगठन की तरफ से पेश हुए वकील अरुण बी वर्गीज ने कहा कि सभी राज्यों में उनके द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स के कारण, पेट्रोल और डीजल के दाम अलग-अलग हैं। उन्होंने मांग की कि पेट्रोलियम पदार्थों पर एक समान कर की व्यवस्था हो। याचिका में यह भी कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें इस पर अपनी विवशता बताती है, लेकिन पेट्रोलियम कंपनियां चुनाव से ठीक पहले तेल की कीमतों में कटौती भी करती है।

याचिका के मुताबिक, 'फिलहाल, अलग-अलग राज्यों में तेल की कीमतों की दर अलग-अलग हैं और यह राज्य सरकारों की खंडित टैक्स पॉलिसी के तहत लगाए गए टैक्स की अलग दर के कारण है। यह संविधान के अनुच्छेद-279 (ए) 6 के तहत सुसंगत राष्ट्रीय बाजार के सामंजस्य में बाधा की तरह है।' इसमें कहा गया है कि एक लीटर पेट्रोल या डीजल की कीमत में राज्य और केंद्रीय करों का कम से कम 60 फीसदी हिस्सा होता है। याचिका में कहा गया है कि अगर पेट्रोल और डीजल को उएऊ के तहत लाया जाता है, तो पूरे देश में एक सामान मार्केट होगा और इस पर लगने वाली टैक्स की दर अधिकतम 28 फीसदी होगी। जो लोग पेट्रोल-डीजल के प्रत्यक्ष खरीददार नहीं हैं, वे भी लगातार रिकॉर्ड दाम बढ़ने से प्रभावित हैं।

'कीमतों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी जीवन के अधिकार का उल्लंघन'

याचिका के मुताबिक, 'एक कल्याणकारी राज्य ऐसा होना चाहिए, जहां हर कोई बुनियादी सुविधाओं का खर्च वहन कर सके। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी लोगों को भारी दिक्कतों की ओर धकेलती है, जिससे संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत दिए गए उनके जीवन के अधिकार का भी उल्लंघन होता है।' याचिका में केंद्र सरकार, केरल सरकार, पेट्रोलियम सचिव, जीएसटी काउंसिल और तीन बड़ी तेल कंपनियों से जवाब मांगा गया है। यह जनहित याचिका पहली बार जुलाई में दाखिल की गई थी, लेकिन कुछ खामियों के कारण वापस ले ली गई। इससे पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने पीआईएल का विरोध किया था और कहा था कि तेल की कीमत नीतिगत फैसलों का हिस्सा है और न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। केरल हाई कोर्ट ने जून में भी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान जीएसटी काउंसिल से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने पर फैसला करने को कहा था। देश में जीएसटी व्यवस्था एक जुलाई, 2017 से लागू हुई थी। जीएसटी में केंद्रीय कर मसलन उत्पाद शुल्क और राज्यों के शुल्क मसलन वैट को समाहित किया गया था। लेकिन पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। इसकी वजह यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को इन उत्पादों पर टैक्स से भारी राजस्व मिलता है।

भारत के प्राइवेट बैंकिंग बिजनेस में फिर एंट्री की तैयारी में एसएसबीसी

नई दिल्ली। एजेंसी

हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन एक बार फिर भारत के प्राइवेट बैंकिंग बिजनस में एंट्री मारने की संभावनाएं तलाश रहा है। लंदन मुख्यालय वाले इस बैंक ने 6 साल पहले भारत में निजी बैंकिंग सेवा बंद करने का फैसला किया था। कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने यह जानकारी दी है। कंपनी ने ग्रोथ के लिए एशिया और वेल्थ मैनेजमेंट को अपना मुख्य आधार बनाने की योजना बनाई है। बैंक की इस रणनीति की अगुवाई ग्रुप सीईओ Noel Quinn कर रहे हैं। उसकी योजना 2025 तक एशिया का टॉप वेल्थ मैनेजर बनने की है। इसके लिए वह वेल्थ और पर्सनल बैंकिंग बिजनस में 3.5 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। बैंक के वेल्थ एंड पर्सनल बैंकिंग के सीईओ ज्ल्हद ईंदे ने कहा कि हम प्राइवेट बैंकिंग में विस्तार करना चाहते हैं।

2015 में किया था भारत से किनारा

प्एँ के लिए एशिया सबसे बड़ा रीजन है और पिछले साल बैंक के एडजस्टेड ग्लोबल रेवेन्यू में वेल्थ एंड पर्सनल बैंकिंग यूनिट का हिस्सा 44 फीसदी यानी 22 अरब डॉलर था। बैंक ने 2015 में भारत में प्राइवेट बैंकिंग बिजनस से किनारा कर लिया था। भारत के आकर्षक लेकर बेहद प्रतिस्पर्द्धी मार्केट से अब तक कई विदेशी बैंक अपना कारोबार समेट चुके हैं। उन्होने कहा कि हम अमीर कस्टमर्स को बैंकिंग सेवाएं देना चाहते हैं। अभी हम भारत में इंश्योरेंस और एसेट मैनेजमेंट के विस्तार पर काम कर रहे हैं। अभी हम वहां प्राइवेट बैंकिंग में नहीं हैं। इसके लिए हमें इसी साल कोई फैसला लेना होगा। अभी प्एँ का सिंगापुर, लंदन और मिडल ईस्ट जैसे ग्लोबल हब्स से अमीर भारतीयों को बैंकिंग सेवाएं दे रहा है। बैंक सिंगापुर और साउथईस्ट एशिया में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। अगस्त में बैंक ने फ्रांस की इंश्योरेंस कंपनी AXA के सिंगापुर एसेट्स को 57.5 करोड़ डॉलर में खरीदा था।

HSBC
Hongkong and Shanghai Banking Corporation

ग्लासगो में उत्सर्जन मुक्त कारों के लिए लक्ष्य निर्धारित

ग्लासगो। एजेंसी

कुछ देशों और कंपनियों के समूह ने 2040 तक उत्सर्जन मुक्त कारों के लक्ष्य को हासिल करने की योजना की घोषणा की है। ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन से इतर बुधवार को यह घोषणा की गयी। कनाडा, चिली, डेनमार्क, भारत, न्यूजीलैंड, पोलैंड, स्वीडन, तुर्की और ब्रिटेन आदि देशों ने इसका समर्थन किया। फोर्ड, जनरल मोटर्स, मर्सिडीज बेंज और वोल्वो कंपनियों और अमेरिका के कई राज्यों तथा शहरों ने भी इस योजना पर हस्ताक्षर किये। वोल्वो जैसी कुछ कंपनियां पहले ही कंबस्चन इंजनों को चरणबद्ध तरीके से उपयोग से बाहर करने के लक्ष्य तय कर चुकी हैं। कुछ देश इसी तरह के इंजन से चलने वाले ट्रकों और बसों के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का संकल्प ले रहे हैं।

सीमा शुल्क विभाग ने जनवरी-अक्टूबर में जब्त खतरनाक सामान की 1,700 खेपों का निपटान किया

नयी दिल्ली। एजेंसी

सीमा शुल्क विभाग ने जनवरी से अक्टूबर 2021 के बीच जब्त किए गए खतरनाक सामानों की 1,700 खेपों का निपटान किया है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्देश दिया है कि निपटान की प्रक्रिया की निगरानी की जाए और इसे तेजी से पूरा किया जाए। इसके अलावा सीमा शुल्क के तहत अन्य प्रभाग भी संबंधित विभागों (राज्य सरकारों सहित) के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करें कि खतरनाक सामग्री का 90 दिन की अवधि के भीतर निपटान किया जाए। बयान में कहा गया है, ''जनवरी, 2021 और अक्टूबर, 2021 के बीच सीमा शुल्क क्षेत्रों से सुरक्षित या जब्त किए गए खतरनाक सामानों की 1,700 से अधिक खेपों का सुरक्षित तरीके से निपटान किया गया है।'' रसायन, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट आदि सहित अस्पष्ट या लावारिस या जब्त खतरनाक सामान की खेपों का निपटान, सीमा शुल्क विभाग के स्थानों पर किया जाने वाला एक सतत अभ्यास है। इनमें अक्सर ऐसा सामान होता है जिनका आयात मौजूदा नीति के अनुसार अंकुश के तहत आता है और उनके आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे सामान प्रतिबंधित सामग्री की प्रकृति के भी हो सकते हैं जिन्हें आयात करने की अनुमति नहीं है, जिन्हें देश में तस्करी करने का प्रयास किया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के जब्त खतरनाक सामान को एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें अपील के प्रावधान भी होते हैं, जिससे निपटान प्रक्रिया में अधिक समय लगता है।

News यू केन USE

रिजर्व बैंक ने डाइनर्स क्लब पर लगी रोक हटाई, नए ग्राहक जोड़ने की अनुमति दी

मुंबई। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल पर लगी पाबंदियां हटाने के साथ ही उसे नए घरेलू ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने की भी मंगलवार को अनुमति दे दी। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि डाइनर्स क्लब पर लगी पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है। ''हमारे परिपत्र के अनुपालन की दिशा में डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से उठाए गए संतोषजनक कदमों को देखते हुए नए घरेलू ग्राहक जोड़ने पर लगाई गई रोक तत्काल प्रभाव से हटा ली गई है।'' केंद्रीय बैंक ने गत 23 अप्रैल को डाइनर्स क्लब को अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहक जोड़ने से रोक दिया था। यह कदम भुगतान प्रणाली डेटा के भंडारण संबंधी मानकों का पालन नहीं करने पर उठाया गया था। रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 2018 में सभी भुगतान प्रणाली सेवाप्रदाताओं को छह महीने के भीतर यह सुनिश्चित करने को कहा था कि लेनदेन से संबंधित उनके समूचे डेटा या ब्योरे का सिर्फ भारत में ही मौजूद एक प्रणाली में भंडारण हो।

खाने के तेल से कृषि उपकर घटाया और बेसिक ड्यूटी भी शून्य की

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने पिछले एक साल से खाना पकाने के तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क को 2.5 फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया है। इन तेलों पर कृषि उपकर को कच्चे पाम तेल के लिए 20 फीसदी से घटाकर 7.5 फीसदी और कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल के लिए 5 फीसदी कर दिया गया है। उपरोक्त कटौती के परिणामस्वरूप, कच्चे पाम तेल के लिए कुल शुल्क 7.5 फीसदी और कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल के लिए 5 फीसदी है। आरबीडी पामोलिन ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल पर बेसिक ड्यूटी मौजूदा 32.5 फीसदी से घटाकर 17.5 फीसदी कर दी गई है। कटौती से पहले कच्चे खाद्य तेलों के सभी रूपों पर कृषि उपकर 20 फीसदी था। कटौती के बाद क्रूड पाम ऑयल पर 8.25 फीसदी, क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर 5.5 फीसदी शुल्क लगेगा।

उद्योग क्षेत्र में कम कार्बन उत्सर्जन के रास्ते पर बढ़ना बेहद अहम है: भारत

ग्लासगो। एजेंसी

भारत ने मंगलवार को कहा कि उद्योग क्षेत्र में कम कार्बन उत्सर्जन वाले विकास मार्गों पर बढ़ने का प्रयास करना पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बहुत अहम है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ग्लासगो में सीओपी26 से इतर 'लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन (लीडआईटी) समिट 2021' को संबोधित करते हुए कहा कि कुल कार्बन उत्सर्जन में औद्योगिग क्षेत्र की भागीदारी करीब 30 फीसदी है। यादव ने कहा, ''कुल कार्बन उत्सर्जन में उद्योग क्षेत्र की भागीदारी करीब 30 फीसदी है, इसलिए उद्योग क्षेत्र में कम कार्बन उत्सर्जन के रास्तों को अपनाने के प्रयास करना पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिहाज से बेहद अहम है।'' यादव ने कहा कि अमेरिका, ऑस्ट्रिया और इथियोपिया जैसे देश और स्कांसा, हिडेलबर्ग सीमेंट जैसी कंपनियां इस पहल में शामिल हुई हैं तथा यह आवश्यक है कि भारी उद्योग की और कंपनियां इस वैश्विक पहल से जुड़ें।

सरकारी तेल कंपनियां 22,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन लगाएंगी

पेट्रोल पंपों पर मिलेगी सुविधा

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

आने वाले दिनों में सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों के पंप पर आप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज कर सकेंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और पब्लिक सेक्टर की दो दूसरी पेट्रोलियम कंपनियां अगले तीन से पांच साल के दौरान देशभर में करीब 22,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाएंगी। इससे भारत के 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के टारगेट को हासिल करने में मदद मिलेगी।

तीन साल में करीब 10,000 पेट्रोल पंपों पर होगी सुविधा

खबर के मुताबिक, देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल के चेयरमैन श्रीकांत वैद्य ने कहा कि हम अगले तीन साल में करीब 10,000 पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग सुविधा स्थापित करेंगे। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने अगले पांच साल में 7,000 और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि। (एचपीसीएल ने 5,000 चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना बनाई है।

भारत ने 2030 तक रखा है ये लक्ष्य

जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी-26) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक भारत के नेट-जीरो एमिशन के लक्ष्य को रेखांकित किया था। इसके अलावा भारत ने 2030 तक कम-कार्बन उत्सर्जन वाली बिजली क्षमता को 50,000 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। भारत का इसके जरिये अपनी कुल ऊर्जा जरूरत का 50 प्रतिशत पूरा करने का टारगेट है। इसके अलावा भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को भी 45 प्रतिशत तक घटाने का टारगेट (लक्ष्य) रखा है।

आईओसी अगले साल तक 2,000 चार्जिंग स्टेशन लगाएगी

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि आईओसी ने अगले साल तक करीब 2,000 चार्जिंग स्टेशन स्थापति करने का लक्ष्य रखा है। वहीं इसी अवधि में बीपीसीएल और एचपीसीएल की 1,000-1,000 चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीपी के साथ मोबिलिटी संयुक्त उद्यम ने पिछले महीने महाराष्ट्र में अपना पहला खुदरा आउटलेट शुरू किया है। यहां पर ईवी चार्जिंग और बैटरी अदला-बदली सुविधा भी उपलब्ध होगी।

बीपीसीएल 7000 चार्जिंग स्टेशन खोलेगी

बीपीसीएल के चेयरमैन अरुण कुमार सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य 7,000 चार्जिंग स्टेशन खोलने और बढ़ने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को मदद करने का है। इन स्टेशनों को 'एनर्जी स्टेशन' के नाम से जाना जाएगा। वहीं, आईओसी की योजना हर 25 किलोमीटर पर 50 किलोवाट का ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने की है। कंपनी हर 100 किलोमीटर पर 100ै हेवी-ड्यूटी चार्जर लगाएगी।

नेट जीरो एमिशन के लिए कंपनियां उठा रहीं कदम

वैद्य ने कहा कि हमारी सभी रिफाइनरियां प्रोडक्शन के हिसाब से शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लिए कदम उठा रही हैं। हम इसके बारे में जल्द घोषणा करेंगे। पुरी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लासगो में 'पंचामृत' घोषणा के तहत 2030 तक अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक घटाने के लक्ष्य के मुताबिक देश की पेट्रोलियम कंपनियों ने मिशन के रूप में 22,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है।

2.5 किलो के पैकेटबंद आटे या चावल में 1 किलो की क्या है कीमत

अब लिखा होगा पैक पर

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

अगर कोई ग्राहक आटे की 3.5 किलो की बोरी या बिस्किट का 88 ग्राम का पैकेट खरीदता है तो उसके लिए यह पता लगाना मुश्किल है कि वह उत्पाद, अन्य उत्पादों की तुलना में महंगा है या सस्ता। लेकिन अगले साल अप्रैल से उपभोक्ताओं के लिए ऐसे किसी सामान की प्रति इकाई की कीमत का पता लगाना बहुत आसान हो जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 'विधि माप विज्ञान (पैकेटबंद वस्तुएं) नियम, 2011' में संशोधन किया है, जिसके तहत कंपनियों के लिए पैकेटबंद सामान के पैक पर 'प्रति इकाई बिक्री मूल्य' को छापना जरूरी हो जाएगा। उपभोक्ताओं को खरीद के संबंध में सचेत निर्णय लेने में मदद करने के साथ-साथ उद्योग के कारोबारियों पर अनुपालन बोझ कम करने के लिए मंत्रालय ने यह कदम उठाया है।

एमआरपी के साथ रहेगा 'प्रति इकाई बिक्री मूल्य'

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि एक किलोग्राम से अधिक की मात्रा का पैकटबंद सामान बेचने वाली कंपनियों को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के साथ प्रति किलोग्राम या जिस भी इकाई के हिसाब से बिक्री की जाएगी, उसका 'इकाई बिक्री मूल्य' दर्शाना होगा। उदाहरण के लिए, 2.5 किलो के एक पैकेटबंद आटे की बोरी पर कुल एमआरपी के साथ प्रति किलो इकाई बिक्री मूल्य को भी छापना और दर्शाना होगा। इसी तरह एक किलो से कम मात्रा में पैकेटबंद वस्तु के पैक पर उत्पाद के कुल एमआरपी के साथ प्रति ग्राम 'इकाई बिक्री मूल्य' छापना होगा।

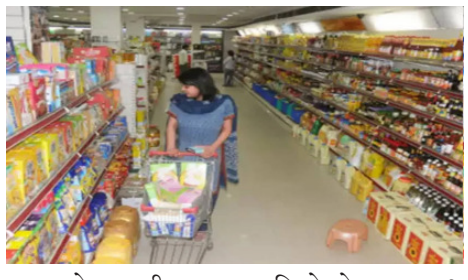

यह नियम किया रद्द

अनुपालन आवश्यकताओं को आसान बनाने के लिए, मंत्रालय ने नियमों की अनुसूची 2 को रद्द कर दिया है जिसके तहत 19 प्रकार की वस्तुओं को एक निर्दिष्ट तरीके से वजन, माप या संख्या द्वारा मात्रा में पैक किया जाना था। उस नियम के अनुसार, चावल या आटे को 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो, 1.75 किलो, 2 किलो, 5 किलो और उसके बाद 5 किलो के गुणकों में पैक करना जरूरी था।

ग्राहक और उद्योग को ये फायदा

अधिकारी ने कहा, 'लेकिन, उद्योग अलग-अलग मात्रा में बेचना चाहता था और मंत्रालय से मंजूरी मांग रहा था। कुछ को मंजूरी दी गई और कुछ को नहीं। नियमों को लचीलापन देने के लिए, उसकी अनुसूची दो को खत्म कर दिया गया है और, हम यूनिट बिक्री मूल्य की अवधारणा सामने लाए हैं।' अधिकारी के अनुसार, यह निर्णय खरीद-बिक्री के बेहतर तौर-तरीकों पर आधारित है और यह उद्योग पर अनुपालन बोझ को कम करेगा और साथ ही उपभोक्ताओं को खरीदारी के संबंध में निर्णय लेने से पहले उत्पाद की कीमत का पता लगाने में मदद करेगा।

एमआरपी से जुड़ा यह नियम बदला

नियमों में किया गया दूसरा बदलाव पैकेज्ड कमोडिटी पर एमआरपी प्रिंट करने का तरीका है। वर्तमान में नियमों में उल्लिखित प्रारूप में एमआरपी मुद्रित नहीं होने पर कंपनियों को नोटिस जारी किए जाते हैं। वर्तमान प्रारूप है कि अधिकतम या अधिकतम खुदरा मूल्य XX.XX रुपये छपा हो लेकिन यदि किसी कंपनी ने दशमलव के पहले के मूल्य का ही उल्लेख किया है और दशमलव के बाद के .XX रुपये का उल्लेख नहीं किया है तो उसे नियमों का उल्लंघन माना जाता है और नोटिस जारी किए जाते हैं। अधिकारी ने कहा, ''अब, हमने कंपनियों से भारतीय रुपये में कीमत लिखने को कहा है और उन्हें किसी भी निर्धारित प्रारूप से मुक्त कर दिया है।''

इन दो नियमों में भी बदलाव

उन्होंने कहा कि नियमों में किया गया तीसरा बदलाव पैकबंद सामान पर 'संख्या' या 'यूनिट' में सामान की मात्रा का उल्लेख करने के संबंध में है। नियमों में किया गया चौथा और आखिरी बदलाव पैकटबंद आयातित जिंस को लेकर है। मौजूदा समय में कंपनियों के पास या तो आयात की तारीख या निर्माण की तारीख या प्रीपैकेजिंग की तारीख का उल्लेख करने का विकल्प होता है। अधिकारी ने कहा, ''अब, ऐसा कोई विकल्प नहीं होगा। कंपनियों को केवल निर्माण की तारीख का उल्लेख करना होगा जो उत्पाद खरीदते समय उपभोक्ताओं के लिए मायने रखती है।'' विधिक माप विज्ञान (पैकटबंद वस्तुएं) नियम 2011 में अंतिम संशोधन जून, 2017 में किया गया था।

वित्त वर्ष 22 की पहली छमाही में आरएसडब्ल्यूएम को परिचालन से 1695 करोड़ रुपये की आय, 120% की वार्षिक बढ़ोतरी

186 करोड़ रुपये रहा एबिटा, सालाना आधार पर एबिटा मार्जिन में 11% की वृद्धि, कर पश्चांत लाभ 82 करोड़ रुपये रहा

■कंपनी का शानदार बिक्री प्रदर्शन जारी, वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही के 769 करोड़ रुपये के मुकाबले वित्त वर्ष 22 की पहली छमाही में 120% इजाफे के साथ राजस्व बढ़कर 1695 करोड़ रुपये हुआ। ■वित्त वर्ष 22 की पहली छमाही में एबिटा सकारात्मक रहा- पिछले वर्ष के 30 करोड़ रुपये के घाटे के मुकाबले इस बार 186 करोड़ रुपये का शानदार मुनाफा ■वित्त वर्ष 21 की पहली छमाही के 83 करोड़ रुपये के घाटे के मुकाबले वित्त वर्ष 22 की पहली छमाही में कर बाद मुनाफा 81.66 करोड़ रुपये ■ब्राउनफील्ड और ग्रीनफिल्ड विस्तार के लिए 330 करोड़ रुपये का कुल पूंजीगत खर्च ■कंपनी ने पहले चरण में 80 करोड़ रुपये के शुरुआती निवेश के साथ निट्स कारोबार में प्रवेश करने की योजना बनाई है ■डेनिम, निट और कॉटन यार्न में निवेश से वित्त वर्ष 23 तक लगभग 575 करोड़ रुपये का राजस्व बढ़ने की उम्मीद।

नई दिल्ली। आरएसडब्लूएम लिमिटेड ने 30 सितंबर, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए अपने वित्तीय नतीजों की घोषणा की। आरएसडब्लूएम लिमिटेड, भारत के सिंथेटिक और मिश्रित स्पन यार्न के सबसे बड़े निर्माताओं और निर्यातकों में से एक है।

वित्त वर्ष 22 की पहली छमाही और दूसरी तिमाही के लिए वित्तीय और कारोबारी परिदृश्य - आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड ने एक मजबूत कारोबारी प्रदर्शन करते हुए वित्त वर्ष 22 की पहली छमाही में 82 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ (पीएटी) अर्जित किया, जो कि पिछले वित्त वर्ष 21 की पहली छमाही के दौरान हुए 83 करोड़ रुपये के नुकसान के मुकाबले शानदार प्रदर्शन है। वित्त वर्ष 22 के शुरुआती महीनों में जारी लॉकडाउन के बावजूद वित्त वर्ष 22 में सकारात्मक रुझानों और बाजार में आई रिकवरी की वजह से साल की पहली छमाही में बिक्री और मुनाफे को दर्शाता है।

कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन की वजह से लगे प्रतिबंधों के बावजूद आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड ने वित्त वर्ष 21 की समान अवधि के मुकाबले वित्त वर्ष 22 की पहली छमाही में 1695 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। समूह के भीतर, आरएसडब्ल्यूएम यार्न व्यवसाय में वित्त वर्ष 22 की पहली छमाही में मांग में अचानक वृद्धि दर्ज की गई। प्रतिबंधों में ढील के साथ, मौजूदा ग्राहकों से बढ़ती मांग की बदौलत डेनिम व्यवसाय ने बेहतर प्रदर्शन किया और इस ट्रेंड में तेजी देखी गई, जो समूह के मजबूत कारोबारी प्रदर्शन में नजर आया। आरएसडब्ल्यूएम ने अपनी व्यावसायिक योजनाओं की भी घोषणा की, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन, विनिर्माण क्षमता निर्माण और विकास की राह पर बने रहने और मजबूत वित्तीय प्रदर्शन जारी रखने के लिए 330 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है। निवेश आवंटन सभी इकाइयों में डेनिम फैब्रिक निर्माण क्षमता, कॉटन मेलेंज यार्न निर्माण क्षमता और आधुनिकीकरण और संतुलन उपकरणों के विस्तार का समर्थन करेगा। रणनीतिक हस्तक्षेपों और केंद्रित प्रयासों के साथ, आरएसडब्ल्यूएम ने अपने डेट इक्विटी रेशियो को 31 मार्च 18 के 1.56 से सुधारकर 30 सितंबर 21 को 0.92 करने में सफल रहा है। पिछले 4.5 वर्षों में, ण 31 मार्च 18 के 1402 करोड़ रुपये से कम होकर 31 सितंबर 21 को 612 करोड़ रुपये हो गया।

मौजूदा स्थिति और परिदृश्य

आरएसडब्ल्यूएम वित्त वर्ष 22 की तीसरी तिमाही में निरंतर मजबूत व्यावसायिक प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा है। स्थानीय लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू के शुरुआती प्रभाव के बावजूद, जिसने वित्त वर्ष 22 की पहली तिमाही में डिस्पैच को प्रभावित किया, बढ़ते टीकाकरण के कारण उपभोक्ता भावनाओं और बाजार के विश्वास में सुधार हुआ है। इसके साथ ही विनिर्माण संयंत्रों में परिचालन सामान्य रहा। इसके अलावा, संगठित खुदरा, उत्सव समारोहों, अनुकूल जनसांख्यिकी और बढ़ते आय स्तर की फैलती पैठ से कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन परिधान खरीद में तेज वृद्धि दर्ज होने के बाद कपड़ा की मांग बढ़ने की उम्मीद है। इसके साथ, महामारी ने टेक्निकल टेक्स्टाइल्स की मांग भी बढ़ा दी है। इसके अतिरिक्त, कंपनी खारीग्राम (राजस्थान) में अपनी सबसे बड़ी इकाई में मेलान्जी यार्न के 30,000 स्पिंडल स्थापित करेगी और मोर्डी (बांसवाड़ा) में यार्न सुविधा में कॉम्बेड कॉटन के लिए 20,000 स्पिंडल भी स्थापित करेगी। ये गतिविधियां वित्त वर्ष 22 में सभी स्थानों पर आधुनिकीकरण और संतुलन उपकरण के अतिरिक्त है।

डेनिम कारोबार

वैश्विक उद्योग पूर्वानुमान को देखते हुए डेनिम कारोबार के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। इसके अलावा, कंपनी को रिसाइकल्ड डेनिम की मांग के कारण डेनिम बाजार में नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। आरएसडब्ल्यूएम के ग्राहकों के पोर्टफोलियो में महत्वपूर्ण वैश्विक ब्रांडों को शामिल करने से आने वाले वर्षों में विकास को लेकर आशावादी रुख का निर्माण हुआ है। कंपनी कचरे के पुनर्चक्रण और इसे पहनने योग्य वस्तुओं में परिवर्तित करके पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने सतत प्रयासों को भी मजबूत कर रही है। पर्याप्त नकदी उत्पादन ने कंपनी को तरलता के मामले में बहुत ही आरामदायक स्थिति में ला दिया है। डेनिम में निवेश के लिए मोर्डी में शीट डाइंग और फिनिशिंग क्षमता के लिए 8.4 मिलियन मीटर डेनिम क्षमता की निर्माण सुविधा के लिए आवंटित किया गया। नतीजों पर अपनी बात रखते हुए, आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक रिजू झुनझुनवाला ने कहा, 'वित्त वर्ष 2021 व्यवसाय के मामले में सीखने और चुनौतियों से भरा था और महामारी से जूझ रहा था जिसने बदलाव के लिए उत्प्रेरक का काम किया। आरएसडब्ल्यूएम उन कंपनियों के बीच खड़ा था, जिन्होंने बदलाव की कल्पना की और अत्यधिक अप्रत्याशित पारिस्थितिकी तंत्र में बेहतर वित्तीय आंकड़ें प्रदान करना जारी रखने के लिए तैयार होने की दक्षता का प्रदर्शन किया। साथ ही वित्त वर्ष 21 हमारे लिए एक बहुत ही संतोषजनक वर्ष था क्योंकि हमने संरचनात्मक परिवर्तन किए, जिसे लेकर हमें विश्वास है कि ये व्यापार विकास के तेज फोकस के लिए महत्वपूर्ण थे। जैसे-जैसे हम विकास के एक नए दौर में कदम रखते हैं, व्यापार विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारी एकीकरण की कोशिश, नए निवेश आवंटन और मुख्य व्यवसाय क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना स्थायी व्यापार विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष 22 की पहली छमाही में मजबूत कारोबारी प्रदर्शन के साथ, हमें विश्वास है कि कंपनी अनुशासित दृढ़ संकल्प के साथ हमारी योजनाओं को क्रियान्वित करते हुए विकास की गति को बनाए रखेगी।''

आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड के विषय में (BSE: 500350, NSE: RSWM)

आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड 78 से अधिक देशों में कुछ सबसे प्रसिद्ध ब्रांडों में उच्च गुणवत्ता वाले यार्न का उत्पादन और आपूर्ति करता है। पिछले 57 वर्षों से, कंपनी उच्च गुणवत्ता वाले कपास, मेलान्जस, सिंथेटिक और नॉवेल्टी यार्न के साथ-साथ सूटिंग और डेनिम कपड़े का उत्पादन कर रही है जिसका उपयोग दुनिया भर में आबादी की परिधान संबंधी जरूरतों के लिए किया जाता है। आरएसडब्ल्यूएम भारत से सिंथेटिक और ब्लेंपडेड स्पन यार्न के सबसे बड़े निर्माताओं और निर्यातकों में से एक है।

एलएनजे भीलवाड़ा के विषय में:

एलएनजे भीलवाड़ा समूह की सम्मानित यात्रा वर्ष 1960 में शुरू हुई, जब समूह के संस्थापक एल.एन. झुनझुनवाला ने राजस्थान के भीलवाड़ा में एक कपड़ा (टेक्सुटाइल) मिल की स्थापना की। समूह ने 50 गौरवशाली वर्ष पूरे कर लिए हैं और आज 1961 की वह सिंगल टेक्संटाइल मिल कई संयंत्रों तक फैल चुकी है। समूह ने रणनीतिक रूप से कारोबार का विविधीकरण किया है और कपड़ा, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, बिजली उत्पादन, आईटी-सक्षम सेवाओं, बिजली इंजीनियरिंग परामर्श सेवाओं, ऊर्जा भंडारण समाधान और कौशल विकास में बहु-उत्पादों और सेवाओं के समूह के रूप में बने रहने को लेकर गर्व महसूस करता है।

एलएनजे भीलवाड़ा समूह एक बेहतरीन विविधीकृत समूह है और भारत में कॉर्पोरेट जगत में बड़े प्रतिस्थापन के रूप में खड़ा है। 967 मिलियन अमेरीकी डॉलर का एलएनजे भीलवाड़ा समूह (www.lnjbhilwara.com), 20 उत्पादन इकाइयों का संचालन करता है और यह रणनीतिक रूप से स्थित है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजार तक पहुंच रखने के साथ और वैश्विक स्तर पर 25,000 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देता है। एचईजी लिमिटेड, समूह की प्रमुख कंपनी है और इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल-लोकेशन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड निर्माण संयंत्र है। समूह भीलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड के तहत दो पनबिजली परियोजनाओं का भी मालिकाना हक रखता है। समूह के राजस्व में निर्यात आय की हिस्सेदारी 50इ है। यह सक्रिय रूप से विभिन्न प्रकार के व्यवस्थित रूप से पहचाने गए व्यवसायों में निवेश करके विकास और मुनाफे की तलाश कर रहा है, जिससे यह कपड़ा, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, बिजली उत्पादन, बिजली इंजीनियरिंग परामर्श सेवाओं, आईटी-सक्षम सेवाओं जैसे उद्योगों, ऊर्जा भंडारण समाधान और कौशल विकास जैसे उद्योगों की श्रृंखला में हितों के साथ एक बहु-उत्पाद समूह बन गया है।

सेफ हार्बर

इस दस्तावेज में कुछ भविष्य-संकेती वक्तयव्यह शामिल हैं। ये वक्त व्य प्रबंधन की वर्तमान अपेक्षाओं या धारणाओं पर आधारित हैं और अनिश्चितता और परिस्थितियों में बदलावों के अधीन हैं। वास्तविक परिणाम आर्थिक, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी, तकनीकी और/या नियामक कारकों में परिवर्तन के कारण यहां दिए गए बयानों द्वारा व्यक्त या निहित लोगों से भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड, इसके निदेशकों और किसी भी सहयोगी या कर्मचारी के लिए कोई दायित्व नहीं है, और स्पष्ट रूप से नई जानकारी, भविष्य की घटनाओं, या अन्यथा के परिणामस्वरूप, अपने दूरंदेशी बयानों को अद्यतन करने या बदलने के लिए इस तरह के किसी भी दायित्व को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है।

लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में गुजरात शीर्ष पर कायम

हरियाणा दूसरे, पंजाब तीसरे स्थान पर

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर बरकरार है। यह सूचकांक निर्यात और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जरूरी लॉजिस्टिक सेवाओं की कुशलता का संकेतक है। गुजरात 21 राज्यों की सूची में पहले स्थान है। उसके बाद क्रमशः हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का स्थान है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा सोमवार को जारी लीड्स (लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स) 2021 रिपोर्ट, समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए नीतिगत प्रतिक्रिया तैयार करने में मदद करेगी।

सूचकांक का उद्देश्य राज्यों में लॉजिस्टिक संबंधी प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है जो देश के व्यापार में सुधार और लेनदेन लागत को कम करने के लिए जरूरी है। पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी केंद्र शासित क्षेत्रों की सूची में, जम्मू-कश्मीर सूची में सबसे ऊपर है। वहीं केंद्र शासित क्षेत्रों में दिल्ली को शीर्ष स्थान मिला है। पहली लॉजिस्टिक रिपोर्ट 2018 में जारी की गयी थी। पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण रैंकिंग जारी नहीं की गयी थी। गुजरात 2018 और 2019 दोनों ही वर्ष रैंकिंग सूची में पहले स्थान पर था। इस बार शीर्ष 10 की सूची में उत्तर प्रदेश छठे, ओडिशा सातवें, कर्नाटक आठवें, आंध्र प्रदेश नौवें और तेलंगाना 10 वें स्थान पर है। वहीं पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, बिहार, हिमाचल प्रदेश और असम क्रमशः 15वें, 16वें, 17वें, 18वें, 19वें, 20वें और 21वें स्थान पर हैं। समग्र सूचकांक 21 संकेतकों पर आधारित है। सर्वेक्षण मई-अगस्त 2021 के दौरान आयोजित किया गया था। पूरी प्रक्रिया में देशभर के 1,405 लोगों से 3,771 प्रतिक्रियाएं मिलीं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट में जो चीजें रखी गई हैं उनसे अगले पांच साल में लॉजिस्टिक लागत को पांच प्रतिशत तक कम करने का रास्ता साफ हो सकता है। अनुमान के मुताबिक, इस समय लागत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 13-14 प्रतिशत है। गोयल ने कहा कि कारोबार क्षेत्रों के साथ-साथ नागरिकों के लिए सुगमता और सशक्तीकरण के लिहाज से लॉजिस्टिक सेवाओं की कुशलता महत्व रखती है।

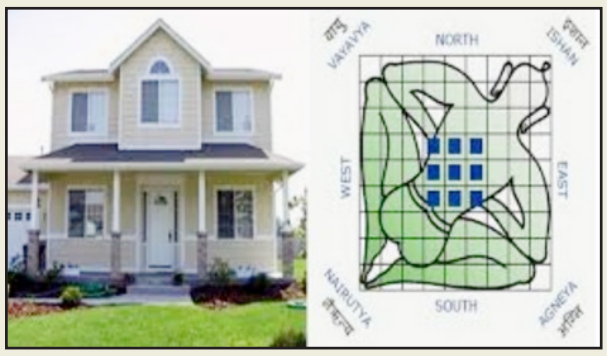

वास्तु दोष से होती है कई बीमारियां उत्पन्न समाधान कर, इन टिप्स का रखें ध्यान

वास्तु विशेषज्ञ संतोष वाधवानी ने बताया कि मानव जीवन में वास्तु दोष जीवन की उन्नति में डालती है बाधा वास्तु दोष का निराकरण करने के लिए लोग अपने घर का इंटीरियल ही नहीं बल्कि अन्य कई उपाय भी करते हैं पिछले कुछ समय में वास्तु शास्त्र की और भी लोगों का काफी रुझान बढ़ा है। माना जाता है कि वास्तु का असर हमारे जीवन और सेहत पर सबसे ज्यादा पड़ता है इसलिए वास्तु शास्त्री मानते हैं कि सेहतमंद रहने के लिए जीवन में बदलाव करना जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि अगर पूर्व दिशा में पैर करके सोते हैं या फिर पश्चिम दिशा में पानी लीक हो रहा है तो यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है अगर घर की ईशान दिशा में गंदगी या फिर जाला कबाड़ या पुरानी चीजें पड़ी हो तो सिर दर्द की समस्या हमेशा बनी रहती है अग्नि कोण में सोने की आदत है तो इसे भी तुरंत बदल लेना चाहिए इससे हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के संकेत मिलते हैं वही वास्तु विशेषज्ञ वाधवानी की मानें तो वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर व्यक्ति संतान संबंधी समस्या से पीड़ित है तो उसे घर के बीचो-बीच सोना चाहिए ऐसा करने से संतान संबंधित समस्या दूर हो जाती है वाधवानी ने बताया कि रसोई में चूल्हे पर खाना बनाते समय महिलाओं का मुंह कभी भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए सूरज पूरब दिशा से निकलता है इसलिए इस दिशा में ही होना चाहिए इसके साथ ही ईशान कोण में बना शौचालय बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है देव स्थान पर बना शौचालय घर की महिलाओं को न सिर्फ बीमार करता है बल्कि संतान सुख की कमी नहीं रहती है इसके साथ ही सोते समय कभी भी अपनी छभी भी नहीं दिखनी आनी चाहिए ऐसा करने से अपनी सेहत का ख्याल रखा जा सकता है।

- संतोष वाधवानी, वास्तु विशेषज्ञ

12 नवंबर 2021 को गोपाष्टमी

जानिए कैसे करें पूजन

प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 12 नवंबर 2021 शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण ने गौ चारण लीला शुरू की थी। गाय को गौमाता भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन मां यशोदा ने भगवान कृष्ण को गौ चराने के लिए जंगल भेजा था। गोपाष्टमी पर गो, ग्वाल और कृष्ण को पूजने का महत्व है।

कैसे मनाएं यह पर्व

■कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन प्रातःकाल में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करते हैं।■प्रातःकाल में ही गायों को भी स्नान आदि कराकर गौमाता के अंग में मेहंदी, हल्दी, रंग के छापे आदि लगाकर सजाया जाता है।■इस दिन बछड़े सहित गाय की पूजा करने का विधान है।■प्रातःकाल में ही धूप-दीप, अक्षत, रोली, गुड़ आदि वस्त्र तथा जल से गाय का पूजन किया जाता है और धूप-दीप से आरती उतारी जाती है।■इस दिन कई व्यक्ति ग्वालों को उपहार आदि देकर उनका भी पूजन करते हैं।■ गायों को खूब सजाया जाता है।■ इसके बाद गाय को चारा आदि डालकर परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद कुछ दूर तक गायों के साथ चलते हैं।■संध्याकाल में गायों के जंगल से वापस लौटने पर उनके चरणों को धोकर तिलक लगाना चाहिए।■ऐसी आस्था है कि गोपाष्टमी के दिन गाय के नीचे से निकलने वालों को बड़ा पुण्य मिलता है।

हर्ष और उल्लास का महापर्व छठ

भारतवर्ष में पर्वों की एक गौरवशाली परंपरा रही है। युगों से भारतीय जनता विभिन्न प्रकार के पर्व-त्यौहार मना रही है। हर धर्म को मानने वालों के अपने-अपने पर्व और त्यौहार हैं। ऐसे सभी त्यौहारों का इतिहास हमारी धार्मिक अथवा सांस्कृतिक भावनाओं से संबंधित है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह सामाजिक वातावरण में सुख-दुःख का अनुभव करता है। खुशी का अनुभव करने के लिए विशेष अवसरों की खोज करता है और त्यौहार उन्हीं में से एक हैं। दीपावली, दशहरा, होली और रक्षाबंधन हमारे प्रमुख त्यौहार हैं, इन्हीं त्यौहारों में से एक प्रमुख त्यौहार है छठ। महाराष्ट्र का गणपति पूजा, गुजरात का गरबा, पंजाब का वैशाखी, असम का बिहू, केरल का ओणम, बंगाल का दुर्गा पूजा, इन त्यौहारों की तरह बिहार का छठ पूजा काफी लोकप्रिय है। छठ पर्व में डूबते व उगते हुए सूर्य की पूजा व आराधना की जाती है। धरती पर जीवन का आधार सूर्य है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार सूर्य आत्मा है तो चंद्रमा बल है। सूर्य पृथ्वी के उत्तरी भूभाग पर करीब नब्बे प्रतिशत रहता है। शेष दक्षिण भाग में समुद्र है इसमें सूर्य उत्तर भाग से दूर होता है, ऐसे में उत्तर भाग के रहने वाले सूर्य को नमन व प्रणाम करते हैं कि वह अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। छठ व्रत पौराणिक काल से ही चला आ रहा है। एक मान्यता के अनुसार महर्षि च्यवन की अस्वस्थता को देखकर उनकी युवा पत्नी सुकन्या ने सर्वप्रथम इस व्रत का शुभारंभ किया था। इस व्रत के प्रभाव से वृद्ध महर्षि पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए थे। तब से आज तक यह व्रत परंपरा में प्रचलित है। विद्वानों का कहना है कि जो व्यक्ति लगातार बारह वर्षों तक सूर्य (छठ) व्रत करता है उसका असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। छठ पर्व को महिलाएं तथा पुरुष दोनों करते हैं।

इस पर्व के प्रारंभ होने के बहत्तर घंटे पूर्व नहा-खाकर एक रस्म के साथ व नियम से छठ व्रत की शुरूआत होती है। पहले ही दिन से महिलाएं शुद्ध जल से स्नान करने के बाद (नहाय-खाय) एक रस्म के साथ छठ पूजा नियम करने लगती हैं। इस दिन से घर के लोग व व्रतधारी महिलाएं छठ के नियम का विधिवत पालन करने लगते हैं। व्रत होने वाले घरों में सफाई-पुताई की जाती है। पूजा का प्रसाद बनाने के लिए घर का एक कमरा सुरक्षित किया जाता है। उसमें केवल व्रत रखने वाले परिजन व महिलाएं ही प्रसाद सामग्री रखने या निकालने के लिए जाती हैं। उसके बाद महिलाएं सादगी, सफाई व पवित्रता का पूरा-पूरा ख्याल रखती हैं। उनका सब कार्य परिवार के सदस्यों से अलग हो जाता है। वे अपना भोजन अलग पकाती हैं। बर्तन, चूल्हा अलग रखती हैं। व्रती जमीन पर ही सोती हैं तथा कंबल या कुश की चटाई जमीन पर बिछाकर ही सोती हैं। पहले दिन सेंधा नमक, घी से बना अखा चावल और कद्दू की सब्जी को प्रसाद के रूप में वे ग्रहण करती हैं। घर के सभी व्यक्ति व्रती के भोजन करने के उपरांत ही भोजन करते हैं। व्रत में स्वच्छता का बहुत महत्व होता है, जिसके चलते साफ-सफाई का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है। पूजा में प्रयोग होने वाला खाद्य पदार्थ शुद्धता के मद्देनजर पकवान बनाने के लिए गेहूं को शुद्ध जल से धोकर छत पर या सुरक्षित स्थान पर सुखाया जाता है। सुखाते समय पूरा ध्यान रखा जाता है कि इसे कोई भी पशु-पक्षी या बच्चे जूठा न करें। उसके उपरांत साफ चक्की में गेहूं को पीसा जाता है। पिसे गेहूं के आटे से व्रती महिलाओं के पकवान जैसे पूड़ी, ठेकुआ तथा अन्य खाद्य सामग्री बनाई जाती है। इस पर्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उपासक महिलाएं निराजल व्रत यानि वह छत्तीस घंटा कुछ भी नहीं खा-पी सकती हैं।

पर्व के शुरू होने के दो दिन बाद व्रती महिलाएं शाम को घाट या पूजा स्थान पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाती हैं। व्रती महिलाएं किसी नदी या तालाब में बने घाट पर पानी में खड़े होकर पूजा विधि पूरा करती हैं तथा सूर्य की उपासना करती हैं। घाट पर छठी मैया की पूजा-अर्चना करती हैं और वेदी पर धूप-दीप व अन्य पूजा सामग्री अर्पण करती हैं।

दूसरे दिन सुबह घाट पर पूजा स्थान पर बहुत जल्दी पहुंचना अनिवार्य होता है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तड़के व्रतधारियों की भीड़ घाटों व पूजा स्थानों पर जुटनी शुरू हो जाती है। इस समय इन स्थानों पर अपना एक अलग ही दृश्य होता है। भक्तगण एक लाईन में खड़े होकर सूर्य के उगने का इंतजार करते हैं और जैसे ही सूर्य दिखाई पड़ता है सूर्य को अर्घ्य देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद व्रतधारी महिलाएं अन्न व जल को ग्रहण करती हैं। एक-दूसरे को प्रसाद बांटती हैं। इस प्रकार चार दिन तक चलने वाले छठ महापर्व का समापन होता है।

छठ पर्व पर करें ये 5 उपाय, होगा महालाभ

1. सूर्य को अर्घ्य दें : ज्योतिष के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य के दोष समाप्त हो जाते हैं। अर्घ्य देने से मान-सम्मान बढ़ता है। शारीरिक रोग दूर होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि सूर्य देव को अर्घ्य देने से वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और अपने भक्त के जीवन को अंधकार से निकालकर प्रकाश (ज्ञान) की ओर लेकर जाते हैं। ज्योतिषविद्या के मुताबिक हर दिन सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति की कुंडली में यदि शनि की बुरी दृष्टि हो तो उसका प्रभाव भी कम होता है। इससे करियर में भी लाभ मिलता है। छठ पर्व को विधिवत मनाने से मिट जाता है सभी तरह का सूर्य दोष।

2. नारियल का उपाय : छह नारियल अपने सिर पर से वार कर जल में प्रवाहित करें। इससे सूर्य ग्रहण का दोष मिट जाएगा।

3. आदित्य हृदय स्तोत्र : आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करें। इससे सूर्य देव प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे।

4. दान : आज गेहूं, गुड़ व तांबे का दान दें। इससे सूर्य ग्रह के दोष दूर होकर वह मजबूत होगा।

5. व्रती की सेवा : इस दौरान जो छठ का व्रत रख रहे हैं उनकी सेवा करें, उनके पैर छूएं। इससे सूर्य देव और छठी मैया प्रसन्न होते हैं।

कब है देव दिवाली, जानिए क्या करते हैं इस दिन

कार्तिक अमावस्या के बाद पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाई जाती है। इस बार 19 नवंबर 2021 शुक्रवार को देव दिवाली मनाई जाएगी। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राचीन समय में इस तिथि पर शिवजी ने त्रिपुरासुर नाम के दैत्य का वध किया था। इसके अलावा मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर ही भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार भी लिया था। इसी दिन सिख गुरु नानकदेवजी का जन्म भी हुआ था। आओ जानते हैं कि क्या करते हैं इस दिन।

1. दीपदान : इस दिन सभी नदी तीर्थ क्षेत्रों में घाटों और नदियों में दीपदान किया जाता है। देव दिवाली देवता मनाते हैं। मान्यताओं के अनुसार देव दीपावली के दिन सभी देवता गंगा नदी के घाट पर आकर दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता को दर्शाते हैं। इसीलिए इस दिन गंगा स्नान कर दीपदान का महत्व है। इस दिन दीपदान करने से लंबी आयु प्राप्त होती है।

2. तुलसी पूजा : इस दिन तुलसी के पौधे और शालिग्राम की पूजा की जाती है। कई राज्यों में तुलसी विवाह होता है।

3. स्नान : इस दिन नदियों में स्नान करने का खास महत्व है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं। स्नान के बाद दीपदान, पूजा, आरती और दान करें। इस दिन गंगा के तट पर स्नान कर दीप जलाकर देवताओं से किसी मनोकामना को लेकर प्रार्थना करें।

4. सत्यनाराण भगवान की कथा : सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें।

रेट्रो, रस्टिक और खूबसूरत : तिस्वा फैमिली की नई लाइट्स

अब जब 2021 में इंडस्ट्रियल स्टाइल की लाइटिंग टॉप लाइटिंग ट्रेंड बन चुकी है, यह निश्चित है कि यह कलेक्शन विजेता के रूप में उभरेगा

पिछले 18 महीनों से लाइटिंग के कई नए ट्रेंड्स ने जोर पकड़ा है, लेकिन इनमें से एक इंडस्ट्रियल स्टाइल की रस्टिक लाइटिंग ने तेजी से अपना मुकाम बनाया है। आकर्षक और बोल्ड दिखने वाली बिग स्टटमेंट लाइट के डार्क शेड में कई ठोस पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी, धातु, रेट्रो फिटिंग के ट्राइपोड स्टाइल के फ्लोर लैंप, ओपन-फेस्ड-फिल्म लाइट, हैंगिंग पेंडेट्स सभी तरह की बिग स्टेटमेंट लाइट फैशन में है। ऊषा इंटरनेशनल का प्रीमियम होम डेकोरेटिव लाइटिंग ब्रैंड तिस्वा अब इन सबके अलावा शैंडलर्स, पेंडेंट्स, वॉल और फ्लोर लैंप की पेशकश करता है, जो स्मार्ट होने के साथ ही रस्टिक भी है। यह किसी भी जगह में प्रवेश करते ही रेट्रो लुक देता है।

एलाएर डब्लूपी14025ई : एलाएर अपनी तरह की अनोखी वॉल लाइट है, जो घर की साज-सज्जा में मौज-मस्ती का फीचर जोड़ती है। खूबसूरत ब्लैक और गोल्ड फिनिश में आकर्षक डिजाइन की लाइटिंग से कमरे की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। चाहे यह लाइट बंद रहे या चाहे खुली रहे, इसकी खूबसूरती की किसी से तुलना नहीं की जा सकती

एक्सटासिस एफपी16023ई एवं टीएल16023ई: यह आधुनिक युग के उपभोक्ता के लिए सबसे अच्छा विकल्प है डेकोरेटिव फ्लोर और टेबल लैंप की एक्सटासिसस फैमिली हमें ओपन फेस की फिल्म लाइटिंग के स्टाइल की याद दिलाती है। यह प्रॉडक्ट तरह तरह के फीचर्स से लैस है, जिसमें इनडायरेक्ट लाइटिंग, आपस में लैंप बदलने और रोशनी को धीमा करने की भी इजाजत मिलती है।

एक्स्टासिस एसपी36010ई: यह बेमिसाल खूबसूरती की झलक देता हुआ पेंडेंट है, जिसमें तीन लाइट हेड होते है। इसकी फिनिशंग ब्लैक, क्रीम, वाइट और वुड से की गई है। एक्सटासिस घर की सजावट की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए फरफेक्ट सोल्यूशन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर की डोम डेकोर थीम क्या है। एक्सटासिस पेंडेंट एक दस्ताने की तरह फिट हो जाता है। आप इसे खूबसूरत ढग से डाइनिंग टेबल पर, अपनी किचन कैबिनेट और घर की लॉबी में भी लगा सकते हैं।

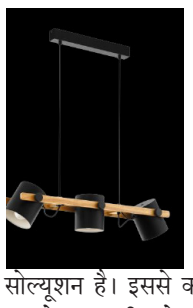

फेलिक्सास एसपी16010ई: यह एक सजावटी पेंडेंट है, जिसकी डिजाइनिंग आधुनिक ढंग और काफी बारीकी से की गई है। इसका देसी लुक और स्टाइल उपभोक्ताओं को अपने घरों को सजाने की इजाजत देता है। आप इसे तीन पेंडेंट के सेट में इस्तेमाल कर सकते हैं या घर के अलग-अलग कोनों में इसे लगा सकते हैं। यह पेंडेंट धीमी एलईडी रोशनी देते हैं। इसके पिछले किनारों पर भी डिमर्स लगे होते हैं ।

कैलड्युरा एसपी12601ई: कैलड्युरा कमरे में बेमिसाल खूबसूरती बिखेरने वाला सजावटी झूमर है, जो कमरे में लाइटिंग की खूबसूरती का आकर्षण का केंद्र बन जाता है। इसकी उभरती हुई शाखाएं कई लाइट हेड्स तक पहुंचती हैं, जिससे यह बेहद खूबसूरत जियोमेट्री का डिजाइन बनता है। यह एक बेहद चमकदार लाइटिंग स्टेटमेंट का पीस है। यह लाइट्स ऑन करने पर आश्चर्यजनक अमूर्त पैटर्न बनाता है। यह लाइट्स लिविंग और डाइनिंग रूम के लिए परफेक्ट है। यह धीमी रोशनी और कम चकाचौंध बिखेरती हैं।

विवराटो डब्लूपी16009ई: यह दीवार पर लगने वली सजावटी लाइट्स हैं, जो अपने आकर्षक और सिंपल डिजाइन के साथ आपके घर में खुशियों की रोशनी भर देती है। ब्लैक और वुडनफिनिश से इसकी खूबसूरती और बढ़ती है। तिस्वा द्वारा यह सलाह दी जाती है कि आप विवराटो को अपने घर के बरामदे में लगाएं। इस लाइट में डिमैबिलिटी की पेशकश की गई है, जिससे गर्म और मन को सुकून देने वाली रोशनी यूजर्स को अपना मूड सेट करने की इजाजत देती है।

फेलिक्सास डब्लूपी16022ई: फेलिक्सास का स्वच्छ, सिंपल और ओपन डिजाइन मन को काफी सुकून पहुंचाता है । चाहे इसे अंदर रखा जाए या बाहर रखा जाए, इसकी जंक प्रतिरोधक बॉडी प्रॉडक्ट की लंबी लाइफ सुनिश्चित करती है। यह प्रोडक्ट डिमैबिलिटी और लैम्स्की को इंटरचेंज करने जैसे लाभ भी प्रदान करता है।

एक्सटासिस डब्लूपी16023ई: डेकोरेटिव वॉल लाइट का ब्लैक और क्रीमी वाइट कलर और वुडन फिनिश घर की खूबसूरती को और बढ़ाता है। यह अपनी परंपरागत देसी फिनिश और स्टाइल से आपके घर को खूबसूरती से सजा-संवार देती है। टास्क लाइटिंग के लिए परफेक्ट यह वॉल लाइट, घर, ऑफिस, किचन और यहां तक कि आंगन में लगाई जा सकती है।

सौर गठबंधन का 2030 तक एक लाख करोड़ डॉलर निवेश जुटाने का लक्ष्य

नयी दिल्ली। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) ने वर्ष 2030 तक एक लाख करोड़ डॉलर का निवेश जुटाने के लिए नॉर्डिक संस्थागत निवेशकों के साथ साझेदारी के अलावा एक निवेश परामर्श समिति के गठन की भी घोषणा की है। आईएसए ने एक बयान में कहा कि इस सलाहकार समिति में अग्रणी संस्थागत निवेशक शामिल होंगे जो गठबंधन को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक लाख करोड़ डॉलर का निवेश जुटाने के लिए निवेशकों को गोलबंद करेंगे। इस राशि का इस्तेमाल वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तरों पर ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा अंतरण और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। इस बयान के मुताबिक, सलाहकार समिति में अफ्रीका 50, सीडीपीक्यू ग्लोबल, आईएफसी, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सदर्न अफ्रीका, कैप्रिकॉर्न इन्वेस्टमेंट ग्रुप और टेमासेक के प्रतिनिधियों को जगह दी गई है। यह समिति सौर गठबंधन के साझेदार बनाए गए डेनमार्क के निवेश फंड आईएफयू, कॉन्किटो और वर्ल्ड क्लाइमेट फंड को कोष जुटाने के लिए मार्गदर्शन देगी। निवेश के लिए साझेदार बनाने के पीछे आईएसए का इरादा वर्ष 2030 तक निर्धारित निवेश को जुटाने की राह आसान बनाना है। उभरते बाजारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सौर ऊर्जा के लिए निजी वित्त जुटाना इसका मकसद है। आईएसए के महानिदेशक अजय माथुर ने कहा, ''सलाहकार समिति के सदस्यों के पास विशाल अनुभव है और उनका मार्गदर्शन हमें विभिन्न क्षेत्रों से निवेश जुटाने में मदद करेगा।'' इसके अलावा आईएफयू, कॉन्किटो और वर्ल्ड क्लाइमेट फंड के साथ साझेदारी भी नए अवसरों की तलाश में मददगार होगी।

भारत में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए 250 करोड़ रुपये का निवेश करेगी एटॉमी

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

दक्षिण कोरिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एटॉमी की भारतीय इकाई एटॉमी इंडिया ने वर्ष 2025 तक भारत में 250 करोड़ रुपये के निवेश से अपनी विनिर्माण इकाइयों की स्थापना की योजना बनाई है। कंपनी इनके जरिये घरेलू बाजार के साथ-साथ निर्यात जरूरतों को पूरा करेगी। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एटॉमी इंडिया के प्रबंध निदेशक शेख इम्तियाज अली ने कहा कि कंपनी की यहां अपनी खाद्य और पूरक आहार श्रृंखला का उत्पादन करने की योजना है और इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विनिर्माण इकाइयों के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। इसके साथ ही एटॉमी ने भारतीय बाजार के लिए अपनी व्यापक योजनाओं का अनावरण करते हुए कहा कि वह वर्ष 2022 तक अपनी ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स (जीएसजीएस) योजना शुरू करेगी, जिसके तहत आयुर्वेदिक भारतीय उत्पादों को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में निर्यात किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि एटॉमी इंडिया ने 10 कोरियाई उत्पादनकर्ताओं के साथ गठजोड़ किया है और उन्होंने भारत में अपनी विकास संभावनाओं के मद्देनजर बेहद रुचि दिखाई है। अली ने कहा, 'अभी परियोजनाएं जारी हैं, हमने कुछ जगहों का दौरा भी किया है। हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के करीब जगह तलाश कर रहे हैं, क्योंकि यहां से वितरण बेहतर होगा।' उन्होंने प्रस्तावित निवेश के बारे में पूछे जाने पर कहा, 'हमारी भारत में 2025 तक विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को लेकर करीब 250 करोड़ रुपये के निवेश की योजना है।'

सितंबर तिमाही में भारत की स्मार्टफोन बिक्री में 5जी उपकरणों का हिस्सा 22 प्रतिशत रहा: सीएमआर

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत की मोबाइल फोन बिक्री में 5जी प्रौद्योगिकी वाले उपकरणों की हिस्सेदारी पिछली तिमाही में बढ़कर 22 प्रतिशत हो गई है। भारतीय मोबाइल फोन बाजार के बारे में साइबर मीडिया रिसर्च (सीएमआर) की तरफ से जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। इसके मुताबिक, जुलाई-सितंबर तिमाही में 5जी तकनीक वाले 20 से अधिक स्मार्टफोन भारतीय बाजार में उतारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक, 5जी फोन की आवक लगातार बढ़ रही है। कीमतों में कमी और उपलब्धता तथा पहुंच बढ़ने की वजह से 5जी स्मार्टफोन की मांग लगातार बढ़ रही है। सीएमआर की विश्लेषक शिप्रा सिन्हा कहती हैं कि वनप्लस, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग और वीवो जैसे स्मार्टफोन ब्रांड अब 5जी फोन को प्राथमिकता दे रहे हैं और उपभोक्ता भी नया फोन खरीदते समय भविष्य की प्रौद्योगिकी को अहमियत दे रहे हैं। इससे 5जी स्मार्टफोन की तेजी बनी रहने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इन पांच बड़ी कंपनियों ने सितंबर तिमाही में तीन अरब डॉलर से अधिक मूल्य के 5जी स्मार्टफोन बेचे हैं। इस श्रेणी में वीवो 18 फीसदी हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर है जबकि सैमसंग 16 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। सीएमआर ने अक्टूबर-दिसंबर 2021 तिमाही में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले पांच-आठ फीसदी की वृद्धि दर का अनुमान पेश किया है। आपूर्ति से जुड़े अवरोध और उपकरणों की लागत बढ़ने से फोन कंपनियों के लिए हालात चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं।

दिसंबर मध्य से कैप्रिकॉर्न एनर्जी के नाम से जानी जाएगी केयर्न एनर्जी

नयी दिल्ली। एजेंसी

ब्रिटेन की तेल और गैस खोज कंपनी केयर्न एनर्जी पीएलसी दिसंबर के मध्य से अपना नाम बदलकर कैप्रिकॉन एनर्जी पीएलसी करेगी। उस समय कंपनी का करीब एक अरब डॉलर का पिछली तारीख का कर विवाद बंद हो जाएगा। केयर्न एनर्जी ने अपनी घरेलू इकाई केयर्न इंडिया को वर्ष 2011 में खनन क्षेत्र के उद्योगपति अनिल अग्रवाल के वेदांता समूह को बेच दिया था। इस समझौते में केयर्न ब्रांड नाम वेदांता को हस्तांतरित करना शामिल था। दोनों कंपनियां एक ही नाम इस्तेमाल कर रही थीं और केयर्न एनर्जी ने इतने समय तक अपना नाम नहीं बदला था। वेदांता समूह ने वर्ष 2018 तक केयर्न इंडिया लिमिटेड नाम से ही कंपनी चलाई। उसके बाद वेदांता लिमिटेड तेल और गैस खोज और उत्पादन का संचालन केयर्न ऑयल एंड गैस के नाम से कर रही है। केयर्न एनर्जी पीएलसी ने एक बयान में कहा, ''कंपनी का नाम केयर्न एनर्जी पीएलसी से कैप्रिकॉन एनर्जी पीएलसी में बदलने की योजना 31 दिसंबर, 2021 से प्रभावी होगी। हालांकि, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी का नाम सीएनई के रूप में ही रहेगा।''

भारतीय कंपनियों ने चीन के शंघाई एक्सपो से दूरी बनाई

बीजिंग। भारत एवं चीन के बीच द्विपक्षीय कारोबार के रिकॉर्ड 100 अरब डॉलर पर पहुंचने की संभावनाओं के बीच चीन का चर्चित आयात एक्सपो भारतीय कंपनियों की अनुपस्थिति में शंघाई में शुरू हो चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने एक वीडियो लिंक के जरिये बृहस्पतिवार को 'चाइना इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपो' (सीआईआईई) का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। एक्सपो में शामिल प्रतिभागियों के मुताबिक, कोविड-19 संबंधी यात्रा पाबंदियों की वजह से दूसरे देशों की अधिकांश कंपनियों एवं फर्मों का प्रतिनिधित्व उनके स्थानीय एजेंटों ने ही किया।

अधिकारियों का कहना है कि चार साल पहले शुरू हुए इस एक्सपो में इस बार भारतीय कारोबारियों के शामिल न हो पाने के पीछे महामारी के दौर में लगी यात्रा पाबंदियां ही मुख्य वजह हैं। पिछले साल से ही चीन ने भारतीय नागरिकों को वीजा देना बंद किया हुआ है और फिलहाल दोनों देशों के बीच उड़ानों का संचालन भी नहीं हो रहा है। इस वजह से चीन के शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले हजारों भारतीय छात्र और सैकड़ों भारतीय कारोबारी एवं परिजन फंसे हुए हैं। वर्ष 2019 के सीआईआईई एक्सपो में केंद्रीय वाणिज्य सचिव अनूप वधावन की अध्यक्षता में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने शिरकत की थी। लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने और दोनों देशों के बीच सीमा पर पैदा हुए तनाव के साथ ही भारतीय कारोबारियों के बीच चीनी बाजार में दखल को लेकर खास दिलचस्पी भी नहीं देखी जा रही है।

बहरहाल, यह एक्सपो ऐसे समय हो रहा है जब भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर के करीब पहुंचने वाला है। कैलेंडर वर्ष के पहले नौ महीनों में ही द्विपक्षीय कारोबार 90 अरब डॉलर के पार जा पहुंचा है। चीन के सीमा शुल्क विभाग के मुताबिक, सितंबर 2021 के अंत में भारत-चीन व्यापार 90.37 अरब डॉलर पर रहा जो एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 49.3 प्रतिशत अधिक है। अनुमान है कि अगले महीने के अंत तक यह 100 अरब डॉलर से अधिक हो जाएगा। चीन के सरकारी समाचार पत्र 'ग्लोबल टाइम्स' में प्रकाशित एक रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है कि इस साल भारत-चीन व्यापार में दर्ज उल्लेखनीय तेजी के बीच एक्सपो में भारत की गैरमौजूदगी एक विरोधाभास है। इस बार एक भी भारतीय कंपनी इस एक्सपो में शामिल नहीं हो रही है। चीन के राष्ट्रपति चिनफिंग ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि चीन बाकी दुनिया के साथ बाजार को साझा करेगा और अपने पड़ोसी देशों से आयात बढ़ाएगा। उन्होंने चीन में मौजूद विशाल मध्यवर्ग का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक बड़ा बाजार है और चीन कारोबार के संतुलित विकास की दिशा में काम करेगा।

डिजिटल पेमेंट पर ग्लोबल हैकाथॉन होगा आयोजित

40 लाख रुपये जीतने का मौका

मुंबई । एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) डिजिटल भुगतान को उपभोक्ताओं के लिए और भी अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अपना पहला ग्लोबल हैकाथॉन आयोजित करने जा रहा है। मंगलवार को आरबीआई ने इस संबंध में बयान जारी कर घोषणा की। 'हार्बिंजर 2021' नाम के इस हैकाथॉन के लिए रजिस्ट्रेशन 15 नवंबर से शुरू होंगे।

डिजिटल पेमेंट से जुड़े समाधान पेश करने होंगे

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस ग्लोबल हैकाथन की घोषणा करते हुए बताया कि हैकाथॉन में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को डिजिटल भुगतान की पहुंच आखिरी व्यक्ति तक करने, इसे और सरल बनाने और इससे जुड़े अनुभव को बेहतर करने के समाधान पेश करने होंगे। इसके साथ ही डिजिटल भुगतान प्रक्रिया को और भी अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने से जुड़े मुद्दों की पहचान कर उनके समाधान बताते होंगे।

विजेता को मिलेंगे 40 लाख, तो रनर-अन को 20 लाख

रिजर्व बैंक के अनुसार, हार्बिंजर 2021 हैकाथन का हिस्सा बनने से प्रतिभागियों के विजेताओं की घोषणा ज्यूरी द्वारा की जाएगी। एक ज्यूरी हर एक वर्ग में विजेताओं का चयन करेगी। पहला स्थान पाने वाले को 40 लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाले (रनर-अप) प्रतिभागी को 20 लाख रुपये की राशि इनाम के तौर पर दी जाएगी।

Kia लाई 6 सीट वाली Carnival 9 सीट वाला मॉडल कर दिया बंद

नई दिल्ली। एजेंसी

दक्षिण कोरिया की कार कंपनी किआ ने भारतीय बाजार में अपनी कार्निवल रेंज को रिवाइज किया है। कंपनी ने Kia Carnival का नया 6 सीट वाला वेरियंट लॉन्च किया है। इस वेरियंट में तीनों रो (पंक्तियों) में कैप्टन सीट्स दी गई हैं। 6 सीट वाली किआ कार्निवल की कीमत 28.95 लाख रुपये है। यह इस कार का दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस है। इसके अलावा, कंपनी ने Carnival का 9 सीट वाला वेरियंट इंडियन मार्केट में डिसकंटीन्यू कर दिया है।

540 लीटर के बूट स्पेस के साथ आया है 6 सीट वाला मॉडल

किआ कार्निवल रेंज अब 6, 7 और 8 सीटर कॉन्फिगरेशंस में आ रही है। 6 सीट वाली किआ कार्निवल में 540 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जो कि 7 और 8 सीट वाले वेरियंट्स से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा, थर्ड-रो सीट्स (तीसरी लाइन की सीटें) और सेकेंड-रो सीट्स (दूसरी लाइन की सीटें) फोल्ड करके बूट स्पेस को क्रमशः 1,624 लीटर और 2,759 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है।

कई सेफ्टी फीचर्स से लैस है किआ कार्निवल

किआ कार्निवल 2.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन से पावर्ड है। यह इंजन 200 ॅप्ज का मैक्सिमम पावर और 440 ऋ का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के जरिए पावर को फ्रंट व्हील्स में ट्रांसमिट किया जाता है। कंपनी का दावा है कि यह श्इ्र 13.9 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो 6 सीट वाली किआ कार्निवल में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, रोल ओवर मिटीगेशन, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, साइड एंड कर्टेन एयरबैग्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, EBD के साथ ABS और डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं।

कार्निवल में दिया गया है 8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

इसके अलावा, र्ख्ं ॅंहर्म्न्ि में थ्ॅं प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और थ्ॅं पोजिशन लैंप, थ्ॅं आइस क्यूब फॉग लैंप, एलईडी टेल-लाइट्स, स्मार्ट पावर टेलगेट, ड्यूल पैनल इलेक्ट्रिक सनरूफ, 3-रो स्लाइडिंग सीट्स, लैपटॉप चार्जर, क्रूज कंट्रोल, ट्रिपल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और 8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे हाई-इंड फीचर्स दिए गए हैं।

बिजली क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति अक्टूबर में 27 प्रतिशत बढ़कर 5.97 करोड़ टन पर

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

बिजली क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति अक्टूबर में 27.13 प्रतिशत बढ़कर 5.97 करोड़ टन पर पहुंच गई। आयात कीमतों में जबर्दस्त बढ़ोतरी के बीच बिजली की मांग बढ़ने से क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति में बढ़ोतरी हुई है। देश के कई ताप बिजली संयंत्र इस समय कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में बिजली क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति 4.68 करोड़ टन रही थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले महीने स्पॉन्ज आयरन क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति में हालांकि 29.2 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 6.5 लाख टन से घटकर 4.6 लाख टन पर आ गई। सीमेंट क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति 6.8 लाख टन से 4.7 लाख टन रह गई। इस्पात और सीमेंट के अलावा अन्य क्षेत्रों को भी कोयले की आपूर्ति घटकर 41.9 लाख टन रह गई, जो एक साल पहले समान महीने में 67.1 लाख टन थी। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने हाल में कोल इंडिया और उसकी अनुषंगियों को यह सुनिश्चित करने को कहा था कि नवंबर के अंत तक ताप बिजली घरों के पास कम से कम 18 दिन का कोयला भंडार रहे। घरेलू कोयला उत्पादन में कोल इंडिया की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक है। कोल इंडिया अस्थायी रूप से बिजली उत्पादकों को कोयले की आपूर्ति में प्राथमिकता दे रही है। जोशी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों के प्रमुखों को इसे हासिल करने के लिए संशोधित लक्ष्य निर्धारित करने और विस्तृत रणनीति बनाने को भी कहा था।

मेटा ने भारत में लघु उपक्रमों को मजबूत करने के लिए 'ग्रो योर बिजनेस हब' शुरू किया

नयी दिल्ली। एजेंसी

मेटा (पूर्व में फेसबुक) ने मंगलवार को 'ग्रो योर बिजनेस हब' शुरू करने की घोषणा की। यह सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) के लिए एक स्थान पर प्रासंगिक जानकारी, उपकरण और संसाधनों पर जानकारी उपलब्ध कराएगा। यह उनके वृद्धि के सफर के आधार पर उनके कारोबार लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। यह घोषणा 'ग्रो योर बिजनेस समिट' के उद्घाटन संस्करण में की गयी जो भारत के लघु और मझोले कारोबार (एसएमबी) के वृद्धि के एजेंडे पर केंद्रित एक कार्यक्रम है। एक बयान में कहा गया है कि हर महीने भारत में लाखों छोटे उपक्रम (अकेले व्हाट्सएप पर 1.5 करोड़) अपनी ऑनलाइन यात्रा शुरू करने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मेटा के अलग-अलग ऐप का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कहा गया फेसबुक और इंस्टाग्राम के कारण इन लघु उद्यमों की वैश्विक पहुंच बढ़ रही है। 30 करोड़ से अधिक लोग फेसबुक पर भारतीय लघु उपक्रमों के पेज को लाइक कर रहे हैं या उन्हें फॉलो कर रहे हैं।

महिंद्रा एंड महिंद्रा की 2027 तक 16 इलेक्ट्रिक वाहन पेश करने की योजना

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

घरेलू वाहन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा कि उसकी 2027 तक एसयूवी और हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलसीवी) श्रेणी में 16 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पेश करने की योजना है। कंपनी इसके जरिये भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वर्ग में अपनी अग्रणी स्थिति को मजबूत करना चाहती है। कंपनी ने 2025 तक अपने कुल राजस्व में 15-20 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने अपनी वृद्धि को तेज करने के लिए या तो निजी इक्विटी निवेशकों को लाने या अपने ईवी कारोबार को एक अलग इकाई का रूप देने के विकल्प को खुला रखा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) पहले ही ईवी में 3,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना की घोषणा कर चुकी है। कंपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी के लिए एक नए ब्रांड नाम पर भी विचार कर रही है जिसे वह 2027 तक पेश करेगी। एमएंडएम के कार्यकारी निदेशक राजेश जेजुरिकर ने कहा, 'एसयूवी वर्ग में

हम 2027 तक 13 नए मॉडल पेश करने पर विचार कर रहे हैं, जिनमें से आठ बिजलीचालित होंगे। हमें लगता है कि 2027 तक हमारे कुल यूवी (यूटिलिटी व्हीकल) का कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों का होगा।' कंपनी 2025-2027 के बीच चार नयी इलेक्ट्रिक एसयूवी पेश कर सकती है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित । संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।